

“दलित समाज में सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक चेतना : मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व का प्रभाव”

1. विकास कुमार, रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़, उत्तर प्रदेश
2. डॉ० ओमप्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़, उत्तर प्रदेश

‘संस्कृति एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तथा कुछ तत्व उसमें सनातन रहते हैं और कुछ काल क्रमानुसार या समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यह तो स्पष्ट है कि भारत जैसे महान देश की प्राचीन संस्कृति का निर्माण किसी एक जाति, धर्म या परम्परा से नहीं हुआ है। कितने ही आचार, विचार और मान्यताओं की कितनी ही नदियाँ इस महासागर में अपना योगदान करती रही हैं। अन्य संस्कृतियों में भी न जाने कितने शाश्वत गुण समाहित होते गये। आर्यों के आने से पहले यहां अनेक निग्रेंटो, प्रोटो, आस्ट्रालॉस्टिक, द्रविड आदि जातियों की एक सम्पन्न संस्कृति थी।¹

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनके द्वारा सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता, समानता और न्याय की व्यवस्था की गई है। जिसके अन्तर्गत भारत के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपना विकास करने का अवसर प्रदान किया गया। जैसे— जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। भारत में लोकतन्त्र के कारण जो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई उससे समाज में व्याप्त असमानता को कम किया गया तथा इसी के साथ—साथ भारत का संविधान भी राज्य को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अर्थात् राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत के नागरिक किसी भी धर्म में अपनी आस्था एवं विश्वास रख सकते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों के कारण भारत के दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के

¹ महीप सिंह एवं चंद्रकांत बांदिबडेकर, साहित्य और दलित चेतना, द्वितीय संस्करण— 2000, प्रकाशक— अभिव्यंजना, काम्पलैक्स लारेंस, दिल्ली—110035, पृ०— 16

नागरिकों को अपना विकास करने का अवसर मिला। क्योंकि यह वर्ग भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही दयनीय स्थिति में था। जिसके कारण इस वर्ग को सामाजिक न्याय भी नहीं मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान धर्म-निरपेक्षता के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है। जिसके कारण भारत में ऐसे लोगों को सुविधाएँ प्रदान करता है जो निर्धन, अशिक्षित तथा बेरोजगार हैं। जिसमें दलितों की दयनीय स्थिति के कारण उन पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इस वर्ग को शिक्षित करने के लिये सरकार ने छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करके इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किये। सन् सत्तर के पश्चात भारतीय समाज में दलित वर्ग ने अपना तेजी से विकास किया जिसमें कांग्रेस सरकार की नीति इनके विकास में सहायक सिद्ध हुई। दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में दलित नेतृत्व ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जो कि यह वर्ग सदियों से शासन सत्ता से वंचित था, वर्तमान समय में यह शासन सत्ता की धुरी बनने की ओर अग्रसरित है। इस वर्ग में राजनीतिक चेतना का लाभ कुछ लोगों को ही मिल सका। जो लोग शिक्षित वर्ग की श्रेणी में थे वे ही अधिकाधिक सुविधाओं का लाभ उठा सके। और जो दलित वर्ग दूर-दराज गाँवों में निवास करता था वे इस लाभ से वंचित रहे। जो कई-कई घण्टे लाईन में खड़े होकर वाट डालने जाते हैं उस दलित वर्ग तक केवल राजनीतिक चेतना ही जागृत हुई तथा शैक्षिक चेतना का अभाव रहा। और दलितों का वह शिक्षित वर्ग सरकार की समस्त सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने विकास में वृद्धि करता रहा। जिसके कारण दलितों में ही एक वर्ग अभिजन वर्ग की श्रेणी में आ गया। क्योंकि ये लोग ही आरक्षण का अस्सी प्रतिशत लाभ उठा रहे हैं और अशिक्षित, गरीब व बेरोजगार दलित वर्ग को आरक्षण का केवल बीस प्रतिशत लाभ ही मिल पा रहा है। वर्तमान समय में दलित चेतना अपने विकास की ओर अग्रसर है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ दलित वर्ग को मिल रहा है जिसके कारण यह शासन सत्ता और निर्णय-प्रक्रिया को कुछ सीमा तक प्रभावित करने लगा है। लेकिन आने वाले समय में दलित चेतना में वृद्धि तो होगी लेकिन इस वर्ग के अशिक्षित व्यक्ति या सुविधाओं से वंचित व्यक्ति की आर्थिक, शैक्षिक

स्तर पर असमानता होने के कारण असहाय महसूस करेंगे जिससे इस दलित वर्ग के मध्य अलगाव की स्थिति बन सकती है तो ऐसी स्थिति पैदा न हो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके सरकारी लाभ देने के लिए वंचितों, अशिक्षितों, निर्धनों एवं बेरोजगार लोगों को वरीयता देनी होगी। ऐसा करने के लिये सरकार को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सन्तान को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन, खान-पान एवं यातायात की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, जबकि गरीब दलित वर्ग अपने बच्चों को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण पिछड़ जाते हैं और सरकारी लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी व्यवस्था करके ही सम्पूर्ण दलित समाज का विकास किया जा सकता है। और इस वर्ग का आर्थिक विकास होने पर समाज में व्याप्त भेदभाव व ऊँच-नीच आदि असमानता अपने आप समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार सामाजिक न्याय प्रदान करने में डा० अम्बेडकर और कार्लमार्क्स की विचारधारा समान है।

भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी यदि किसी एक विशेष उपलब्धि के लिए स्मरणीय रही है तो वह है, राजनीतिक जगत में दलितों के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार करना और उन्हें समान नागरिक के रूप में मताधिकार प्रदान किया जाना। यद्यपि भारत के वैदिक काल में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त थे जिसमें दलित एवं महिलाएँ भी शामिल थी। जिसके कारण वैदिक काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। परन्तु वैदिक काल के पश्चात् जैसे-जैसे समय गुजरता गया वैसे-वैसे ही सामाजिक असमानता बढ़ती गयी जिसके प्रमाण वैदिक काल के पश्चात् आये उत्तर वैदिक काल में प्रमाणिक तौर पर लगाये जाने लगे। जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव पैदा होने लगा।¹ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान के द्वारा दलितों को समान नागरिकों के रूप में अधिकार प्रदान किये गये। परन्तु सदियों से चली आ रही सामाजिक मानसिकता, जो दलितों की समानता को किसी भी क्षेत्र में सहन नहीं कर पाई थी वह इसे राजनीतिक क्षेत्र में कैसे स्वीकार करती। परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता के बाद भी दलितों का भारतीय

राजनीति में प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहा।² 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दलितों को निचले स्तर पर आरक्षण प्रदान करके राजनीतिक चेतना जागृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। डा० अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास हेतु कार्य किये उससे वे दलित वर्ग के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने भारतीय संविधान द्वारा इस वर्ग को अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस परम्परा को आगे चलकर मान्यवर कांशीराम ने अपने राजनीतिक नेतृत्व के स्वपन को पूरा करने का प्रयास किया।³ दलित समाज में राजनीतिक चेतना का प्रचार-प्रसार करके उन्हें एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं बल्कि आरक्षण देने वाला बनेंगे। जिसके लिए राजनीतिक सत्ता का दलितों के हाथों में आना आवश्यक है। उनका विचार था कि दलित वर्ग के जो लोग आरक्षण के बल पर सरकारी नौकरियों में पहुँचे हैं उनके सहयोग से दलित समाज को एक राजनीति मंच प्रदान करना था।⁴

मान्यवर कांशीराम का मानना था कि भारत में असली समाजवाद तब आयेगा जब दलित वर्ग के लोग सामान्य वर्ग की सीट से चुनाव जीतने लगेंगे। जब ऐसी व्यवस्था भारत में स्थापित हो जायगी तो उस समय आरक्षण व्यवस्था को आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था में दलित वर्ग भी निर्भिकता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकेगा जो भारत में एक मजबूत लोकतन्त्र को बनाने में सहायक होगा।⁵ हमारे देश की परम्परा और संस्कृति दलितों के प्रति राजनीति में भाग लेने के विरुद्ध ही रही है जिसके कारण दलितों को सदियों से सत्ता से अलग रखा गया। क्योंकि अन्य वर्गों के लोगों का मानना है कि यदि दलितों के हाथ में सत्ता आ जायेगी तो उनके लिए उसे सही तरह से चलाना सम्भव नहीं होगा। इस विचार का विरोध करते हुए मान्यवर कांशीराम का कहना था कि जब भी दलितों को निर्णायक अधिकार मिले हैं तो उन्होंने लोक

कल्याणकारी नीति को अपनाया है और वे किसी भी समस्या का प्रासंगिक समाधान निकाल सकते हैं। उनका मानना था कि राजनीति समाज के उच्च वर्गों के लिए केवल एक व्यवसाय मात्र है जबकि दलित वर्ग के लिए यह समाज कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जिससे दलितों के दलितपन को दूर कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।⁶

मान्यवर कांशीराम न तो किसी राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते थे और न ही उनका कोई राजनीति गुरु थे। वे किसी बुद्धिजीवी वर्ग से सम्बन्धित नहीं थे और न ही उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था। वे रोपड़ (पंजाब) में दलित सिख परिवार में जन्में थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि पूरे देश में दलितों को एक संगठित मतदाता शक्ति के रूप में उभारकर राजनीतिक शक्ति प्रदान करना था। जिससे की दलित वर्ग की राजनीतिक हैसियत बढ़े।⁷ उनके द्वारा प्रदान किया गया राजनीतिक नेतृत्व दलितों को जोड़ने में अधिकांशतः सफल रहा। सुश्री मायावती (पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) उन्हीं को देन हैं। डा० अम्बेडकर दलितों के देवतुल्य पूज्य बन गये जो कि मान्यवर कांशीराम जी उन्हें अपना आदर्श मानते थे।⁸

दलितों में राजनीतिक चेतना जाग्रत करने के लिए मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को डा० अम्बेडकर के जन्मदिवस पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जो कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में बसपा का उदय वामपंथी आन्दोलन के जवाब में उभरा।⁹ निसंदेह आठवें दशक में हिन्दी भाषी प्रदेशों और महाराष्ट्र में बसपा का उदय हिन्दू सम्प्रदायवाद और उच्चवर्गीय प्रभुत्ता के बढ़ते असर की पृष्ठभूमि में हुआ। जिसका उद्देश्य संसदीय तरीके से राजनीति सत्ता हासिल करना था। आजादी के बाद कांशीराम भारतीय दलितों की सबसे बड़े मसीहा बनकर उभरे जिन्हें अम्बेडकर के बाद दलितों का सबसे बड़ा मसीहा माना गया। क्योंकि मान्यवर कांशीराम का राजनीतिक दर्शन "सत्ता सभी तालों की मास्टर

चाबी है” जो कि उन्होंने डा० अम्बेडकर के दर्शन से गहण की थी यह बात उन्होंने कुछ मायनों में सच कर दिखायी।¹⁰ कांशीराम ने दलित राजनीति को एक नई पहचान उत्तर प्रदेश में सरकार के रूप में दी। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी बसपा की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने दलित क्रान्ति के बीज पूरे भारत में बो दिये जो एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव का संकेत है। उनका मानना था कि वोट का अधिकार व्यक्ति को गुलामी से राहत प्रदान करता है।¹¹

मान्यवर कांशीराम का मानना था कि ‘केवल ईश्वर की दुहाई देकर, मानवीय समानता का उपदेश देकर समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता’। जब तक दलित वर्ग के पास राजनीति सत्ता नहीं आयेगी तब तक उन्हें समाज में न कोई सम्मान देगा, न समानता के अधिकार देगा। उन्होंने निश्चय किया कि जिन लोगों को राजनीति की कोई समझ नहीं, जो सत्ता सुख से सदैव दूर रहे, मैं उन्हें सत्ताधारी बनाऊँगा।¹² उन्होंने देश की दलित राजनीति को नया आधार, नया औजार और नया आकार दिया। जब कांशीराम ने यह नारा लगाया कि “वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा”। तो वे सिर्फ चुनौती नहीं पेश कर रहे थे बल्कि दलिता को उनकी असली ताकत का अहसास भी करा रहे थे।¹³ कांशीराम दलितों को सम्मान और सामाजिक न्याय दिलाना चाहते थे जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके ही दिलाया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी से गठबन्धन किया और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।¹⁴ यह राजनीतिक सफलता दलितों को राजनीतिक चेतना प्रदान करती रही है। भारतीय राजनीति में बसपा को ताकतवर बनाकर उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का उदाहरण पेश किया।¹⁵ लेकिन उनका महत्व दलितों को समुचित भागीदारी के लिए संगठित करने और निर्णायक स्थिति तक पहुचने तक ही सीमित नहीं है भले ही हम उन्हें

अवसरवादी कहे, लेकिन अपनी रणनीति के माध्यम से उन्होंने भारत के परम्परागत सामाजिक ढांचे में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने में सफलता हासिल की। स्वीकार्य तो राजनीति में दलित पहले भी थे, लेकिन तब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की जाती थी, अन्य घटक महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अब अन्य घटक दलितों के साथ जुड़ना चाहते हैं यह प्रक्रिया कांशीराम शुरू करके गये। जिसने भारत में सामाजिक राजनीति समीकरण का एक नया व्याकरण रचा।¹⁶

मान्यवर कांशीराम के व्यक्तित्व की यह विशेषता ही है कि उन्होंने अवसरवादी होने के मत को स्वीकार किया। लेकिन उनके इस अवसर के पीछे उद्देश्य दलित समीकरण रहा, जिसे उनके शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। “हमारा मकसद किसी भी तरह से केन्द्र की सत्ता में आना है, लेकिन जब तक हम अपने पक्ष में 51 प्रतिशत वोट नहीं पा लेते हम इन तमाम राजनीति दलों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे हमारी यह खुली रणनीति है।” हमने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई लेकिन हमें कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि हम उनके कहने पर चले। हाथ हम सबसे मिला सकते हैं लेकिन काम हम अपना करते हैं। हमें लगा की भाजपा आगे बढ़ रही है तो उसे रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलायाँ इससे मान्यवर कांशीराम ने यह सिद्ध कर दिया कि अवसरवादी होना भी दलित राजनीति के हित में है जिससे दलित बार-बार गरिमा के साथ राजनीति हित साध सकते हैं। उनका कहना था कि अवसरवादी होना क्या बुरी बात है? आखिर दलितों को सदियों से अवसर ही कहाँ मिला है।¹⁸

मान्यवर कांशीराम ने डी0एस0-4 के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में डा0 अम्बेडकर के विचारों को उद्धृत कर समाज के लोगो में राजनीति ऊर्जा को संचालित करने में सफलता प्राप्त की। इस देश के दलित समाज को अब यह आवश्यक लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीति दल का गठन हो जो पूर्ण रूप से दलित शोषित समाज के हितों की सुरक्षा का हिमायती हो। अतः

मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। जिससे डी0एस0-4 का नाम परिवर्तित कर देश के सभी दलित शोषित समाज का इसमें प्रवेश का रास्ता खोल दिया जो शोषण व्यवस्था के कुचक्र को अभी तक समझ न सके थे।¹⁹

“मान्यवर कांशीराम का नेतृत्व एवं भारतीय राजनीति में दलित वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव” जो कि मेरा शोध विषय रहा है यह दलित समुदाय में राजनीतिक चेतना को दर्शाता है। जिसे तकपूर्ण बनाने के लिए मेरठ मण्डल के सभी जिलों (मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, पंचशीलनगर, बुलन्दशहर एवं गौतमबुद्ध नगर आदि) से 200 निदर्शनों का चयन आयु, लिंग, शिक्षा, जातिसमूह और व्यवसाय के आधार पर किया गया है। जिसमें 25 प्रश्नों की एक प्रश्नावली भी तैयार की गई थी जिसके आधार पर जनसमूह के विचारों को जानने का प्रयास किया गया व साथ ही स्थानीय नेतृत्व का दृष्टिकोण जानने की भी कोशिश की गई।

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तरदाताओं के वर्गीकरण को एक तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार हैं :-

आयु वर्ष में				लिंग		शिक्षा				जाति समूह				व्यवसाय			
18— 35	36— 50	51— 65	66— ऊपर	पु0	म0	साक्षर		निरीक्षर		एस0 सी0	ओ0 बी0 सी0	सा0	अ0 सं0	नौकरी	कृषि	मज दूर	अन्य
						पुरुष	महिला	पुरुष	महिला								
70	60	40	30	140	60	120	55	20	5	46	56	74	24	40	60	30	70
कुल योग= 200				कुल योग= 200		कुल योग= 200		कुल योग = 200		कुल योग = 200				कुल योग = 200			

1. आयु के आधार पर उत्तरदाताओं को चार भागों में विभाजित किया गया है।

18—35 वर्ष की आयु के 70 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया जो कुल

संख्या का 35 प्रतिशत है। 36–50 वर्ष की आयु के 60 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया, जो कुल संख्या का 30 प्रतिशत है। 51–65 वर्ष की आयु के 40 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। जो कुल संख्या का 20 प्रतिशत है व 65 से अधिक आयु के 30 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया, जो कुल संख्या का 15 प्रतिशत है।

2. लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है पुरुष और महिला/जिसमें 140 पुरुष और 60 महिलाओं से साक्षात्कार किये गये जो कि पुरुषों का 70 प्रतिशत व महिलाओं का 30 प्रतिशत है।
3. शिक्षा के आधार पर भी उत्तरदाताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है साक्षर व निरक्षर। साक्षर व निरक्षर उत्तरदाताओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है पुरुष व महिला। साक्षर उत्तरदाताओं में 120 पुरुषों से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 60 प्रतिशत है। 55 साक्षर महिलाओं से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 27.5 प्रतिशत है।

इसी प्रकार 20 निरक्षर पुरुषों से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 10 प्रतिशत है व 5 निरक्षर महिलाओं से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 2.5 प्रतिशत है।

4. जाति समूह के आधार पर भी उत्तरदाताओं को चार भागों में विभाजित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग। जिसमें 46 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से साक्षात्कार किया गया है जो कुल संख्या का 23 प्रतिशत है। 56 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 28 प्रतिशत है। 74 सामान्य वर्ग के लोगों से साक्षात्कार किया गया जो कुल संख्या का 37 प्रतिशत है। 24

अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से साक्षात्कार किया गया जिसमें, मुस्लिम, इसाई, जैन व बौद्ध को शामिल किया गया जो कुल संख्या का 12 प्रतिशत है।

5. व्यवसाय के आधार पर भी उत्तरदाताओं को चार भागों में विभाजित किया गया है नौकरी पेशा वाले, किसान, मजदूर व अन्य जिसमें 40 साक्षात्कार नौकरी पेशा करने वाले लोगों से किये गये जो कुल संख्या का 20 प्रतिशत है। 60 किसान लोगों से जो कुल संख्या का 30 प्रतिशत है। 30 साक्षात्कार मजदूरी करने वाले लोगों से किये गये जो कुल संख्या का 15 प्रतिशत है। 70 साक्षात्कार 'अन्य' लोगों से किये गये जिसमें छात्र, राजनीतिज्ञ, गृहणी, सेवानिवृत्त व्यक्ति, व्यापारी और समाजसेवी आदि जो कुल संख्या का 35 प्रतिशत है।

निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि मान्यवर कांशीराम ने दलित वर्ग में जो राजनीतिक चेतना का विकास किया है उससे दलितों में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की जिज्ञासा बढ़ी है जो दलित वर्ग के लिए महत्वपूर्ण, रुचिकर एवं हितकारी रहा जो परम्परागत राजनीति की परिधि को लांघकर सत्ता प्राप्ति हेतु क्रियाशील हुआ। दलित वर्ग को एक झंडे के नीचे लाकर एक मंच प्रदान करने का श्रेय मान्यवर कांशीराम को ही जाता है।

संदर्भ सूची

1. बी०आर० अम्बेडकर, 'द अन्टचेबल्स', भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद, द्वितीय संस्करण, 1969, पृ०— 2
2. विनोद अग्निहोत्री, 'कांशीराम और उनकी बसपा', (राजकिशोर सं०) हरिजन से दलित, 2007, पृ०—80
3. ए०आर० अकेला, 'कांशीराम के साक्षात्कार', मानक पब्लिकेशन, दिल्ली, 2007, पृ०— 156

4. आम्बेथ राजन, 'माई बहुजन समाजपार्टी', ए0बी0सी0डी0ई0 प्रकाशन दिल्ली, 1986, पृ0— 8
5. आमप्रकाश बाल्मोकी, 'सदियों का संताप', गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, 2008, पृ0— 45
6. के0एल0 चंचरीक, 'भारत में दलित आन्दोलन एक मूल्यांकन', सृष्टि बुक डिपो प्रकाशन, 1993, पृ0— 53
7. आर0 चन्द्रा व के0एल0 चंचरीक, 'आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003, पृ0— 355
8. के0एल0 चंचरीक, 'आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003, पृ0— 355
9. एच0एल0 दुसाध, 'उ0प्र0 में बसपा की सफलता, सोशल इंजीनियरिंग का कमाल या कुछ और (एक चुनावी अध्ययन), दुसाध प्रकाशन, देवरिया, 2008, पृ0— 48
10. एच0एल0 दुसाध, 'डाइवर्सिटी दलित सशक्तिकरण का सर्वोत्तम औजार, दलित लेखक संघ, नई दिल्ली, 2005, पृ0— 201
11. कांशीराम, 'चमचा युग', समता प्रकाशन, नागपुर, 2006, पृ0— 137
12. कमलाकान्त, 'दलितों के मसीहा कांशीराम का सम्पूर्ण वृत्तान्त, राजा पाकेट बुक्स, बुराडी, दिल्ली, 2007, पृ0— 25
13. अजय कुमार, 'दलित पैंथर आन्दोलन', गौतम बुक सेन्टर दिल्ली, 2006, पृ0— 125
14. अजय कुमार, 'बहुजन नायक कांशीराम के अविस्मरणीय भाषण: गौतम बुक सेन्टर दिल्ली, 2007, पृ0— 37

15. प्रभात कुमार, 'बहुजन समाज के अनमोल रत्न', देवनंदिनी पब्लिकेशन, दिल्ली, 2009, पृ०— 45
16. मायावती, 'मेरे जीवन संघर्ष एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा', भाग—1, ताज प्रिन्टर्स, नई दिल्ली, 2006, पृ०— 47
17. मोहनदास नैमिशराय, 'बहुजन नायक कांशीराम का जीवन संघर्ष', कान्ती पब्लिकेशन, दिल्ली, 2006, पृ०— 42
18. उदित राज, 'दलित आन्दोलन से असली धर्मनिरपेक्षता तक', कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2006, पृ०— 42
19. महीप सिंह व चन्द्रकांत बांदिबडेकर, 'साहित्य और दलित चेतना', अभिव्यंजना प्रकाशन, बी 70/72 डी०एम०आई०डी०सी० काम्पलैक्स, लारेंस रोड दिल्ली, 2000, पृ०— 32